possible to indicate any denite time for realisation of the demands in this case.

Twenty top assessees of Central Excise

3493. SHRI RAMSINGH RATHWA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) what are the names of the twenty top assessees whose Central excise dues are highest showing their confirmed demands and the disputed demands; and

(b) what are the details of the action taken/being for its recovery?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANIL SHASTRI) : (a) and (b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Applicability of Central Excise and Salt Act in the State of Mizoram

3494. SHRI RAMSINGH RATHWA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government had filed a petition in Guwahati High Court for a declaration that the Central Excise and Salt Act, 1944 is applicable in the State of Mizoram; if so, what are the details thereof;

(b) what were the special circumstances for which Government had to file a declaration petition for applicability of a Central Act;

(c) whether there was any ambiguity or doubt about the applicability of the Act in the State; and

(d) if not, what were the reasons for filing the petition ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANIL SHASTRI) : (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

डालमिया उद्योग समूह के परिसरों पर आय कर विभाग के अधिकारियों द्वारा डाले गए छापे

3495. **श्री अनन्त राम जायसवाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा मार्च, 1990 में डालमिया उद्योग समूह के परिसरों पर छापे डाले गए थे; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन छापों के साथ गुजरात हैवी केमिकल्स लिमिटेड, जो डालमिया समूह के साथ संयुक्त रूप से काम कर रही है, की भी तलाशी ली गई;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात हैवी केमिकल्स लिमिटेड में डालमिया समूह की करोड़ों रुपए की अघोषित धनराशि निवेशित है; और

(घ) क्या कर अपवंचकों के विरुद्ध कोई मुकदमे दायर किए गए हैं; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी हां, आयकर अधिनियम की धारा 132 के अधीन दिनांक 15 मार्च, 1990 को तथा उसके परवर्ती दिनों में श्री संजय डालमिया तथा उनसे सम्बन्धित कम्पनियों और व्यक्तियों के मामले में विविध परिसरों की तलाशियां ली गई थीं तथा उनका सर्वेक्षण किया गया था ।

इन तलाशियों के दौरान प्रथम दृष्टया लेखा-बाह्य परिसम्पत्तियां अभिगृहीत की गई हैं, जिनमें 9.58 करोड़ रुपए मूल्य की नकदी, जेवर-जवाहिरात शेयर के कागजात तथा अन्य मूल्यवान वस्तुएं, लेखा पुस्तिकाएं, अपराध आरोपणीय दस्तावेज शामिल हैं। जिन व्यक्तियों की तलाशियां ली गई थीं, उन्होंने आयकर अधिनियम की धारा 132(4) के अधीन 92 लाख रुपए की लेखा-बाह्य आय की घोषणा की है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) तलाशी तथा सर्वेक्षण के दौरान बरामद हुए अपराध आरोपणीय दस्तावेजों से यह पता चलता है कि अनेक कम्पनियों द्वारा गुजरात हैवी केमिकल्स लिमिटेड में काफी बड़ी मात्रा में निवेश किया गया है जो

डालमिया ग्रुप की अघोषित आय को श्वेत आय में परिवर्तित करने का एक साधन-मात्र प्रतीत होता है ।

(घ) मैसर्स जी. टी. सी. इण्डस्ट्रीज के मामले में अभियोजन की शिकायतें दायर की गई हैं । सिक्किम में निगमित पांच कम्पनियों के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम की धारा 148 के अधीन नोटिस जारी किए गए थे ताकि उन कम्पनियों की कर-निर्धारण किए जाने से रह गई आय पर कर लगाने के बारे में कार्यवाही शुरू की जा सके। परन्तु सिक्किम उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी करके इन कार्यवाहियों पर रोक लगा दी है ।

Credit availed of and overdues of primary Agricultural Credit Societies

3496. **SHRI VIREN J. SHAH** : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) what was the extent of credit availed of and also overdues of primary agricultural credit societies during each of the last three years;

(b) what will be the effect of the policy of remitting loans up to Rs. 10,000 on the net credit extended and overdues;

(c) whether any steps are being taken/proposed to be taken to ensure better recovery of loans and significant reduction of overdues in future; and

(d) if so, what are the details thereof and if not, what are the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANIL SHASTRI) : (a) The position of credit availed of by PACS as on 1985, 1986, 1987, 1988 and 1989 and overdues as on the above dates are as under :

(Rupees in crores)

	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5	6
Borrowings . .	3743.12	3927.22	4326.41	4934.43	5427.87*
Overdues . . .	1630.25	1806.08	1896.25	2131 97	2171.15*
%of overdues to demand	44.70	41.30	40.70	40 20	40.00*

*Provisional.

(b) The waiver of loans upto Rs. 10,000/- would reduce the percentage of overdues to demand considerably if the cooperatives also takes necessary steps to recover the dues which had fallen due after 2 October, 1989. The credit availed of by PACS is likely to increase as the beneficiaries of debt relief scheme would become eligible for fresh finance after clearing their overdues to the cooperatives.

(c) and (d) The Cooperative Banks were advised to take necessary steps to recover the dues which are not covered under the Agricultural and Rural Debt Relief Scheme by gearing up their recovery machinery and reorient their lending policies and procedures to ensure proper end use of credit. Further, in terms of the provisions of Agricultural and Rural Debt Relief Scheme, the overdue amount in excess of the amount of relief with a maximum of Rs. 10,000/- as also the overdues outstanding after 2nd October, 1989 are required to be repaid for such borrowers becoming eligible for fresh finance. The State Govts. were also requested to extend necessary support to the Cooperatives in recovering their dues and to create a climate conducive for recovery.

राज्यों में भूतल तथा भूमिगत तल संबंधी संगठनों की स्थापना के लिए केन्द्रीय सहायता

3497. **श्री छोटू भाई पटेल**
श्री अजीत जोगी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या केन्द्रीय सरकार ने